IN THE HIGH COURT OF UTTARANCHAL
AT NAINTIAL
Civil Writ Petition No. 269 of 2002 (S/B)

Shri Bharphoor Singh ……..Petitioner.

Versus

1. State of Uttaranchal through
   Home Secretary, Uttaranchal
2. Director General of Police, Uttaranchal
3. Director General of Police,U.P.
4. Police Mahanirdeshak, Merrut Zone
5. Police Upmahanirdeshak
   Garhwal Range
6. S.S.P.Dehradun. ……..Respondents

Sri Ashok Agarwal, learned counsel for the petitioner
Sri Paresh Tripathi, learned standing counsel for the respondents

Hon'ble B.C. Kandpal, J.

By way of this writ petition, the petition has sought a direction in the nature of mandamus commanding the respondent No. 2 and 3 for making the payment of his post retirement benefits including the pension.

Brief facts giving rise to this petition are that the petitioner was Head Constable in police and retired form services on 31.10.1997. At the time of this retirement, he was posted at Dehradun. The petitioner was initially appointed as Constable on 30.10.1956 in the U.P. Police and subsequently, he was promoted on the post of Head Constable on 27.10.1978.

The petition further reveals that the petitioner was posted at P.S. Mawana District Meerut in the year 1983 and there, a case was registered under Section 409 I.P.C. against him. The order of suspension passed against the petitioner was revoked on 12.11.1987.

It further reveals from the petition that after revocation of the suspension order, the petitioner completed his services upto the year 1997 and during this period there was no stigma against him.

It has been averred in the writ petition that after the retirement of the petitioner the respondents are deliberately and intentionally avoiding to pay the post retirement benefits like pension and gratuity, however they are paying provisional pension which is also not as per the pay scale of the petitioner.

It has also been averred that the petitioner has made several representations to the respondents but no action has been done so far, hence this writ petition.

The counter affidavit has been filed by the respondents pleading therein that the criminal case No. 286 of 1983 under Section 409 I.P.C. is still pending against the petitioner. Therefore, the petitioner is being paid the provisional pension in view of the Uttar Pradesh Civil Service (Tenth Amendment) Regulations, 1983.

The petitioner has filed the rejoinder affidavit stating therein that there is another Government Order of the year 1989, which envisages that the pension of the Government servant cannot be retained during the pendency of any criminal proceeding.

Heard leaned counsel for the parties and perused the record.

Sub Rule- 2 of Uttar Pradesh Civil Service (Tenth Amendment) Regulations, 1983 regards as follows:-

> *"The provisional pension shall be authorized for the period commencing form the date of retirement up to and including the date of which after the conclusion of departmental or judicial proceedings or the enquiry by the Administrative Tribunal, as the case may be final orders are passed by the competent authority."*
>
> *Again Sub-Rule 3 of the above said Rule reads as follows:*
>
> *"No date-cum-retirement gratuity shall be paid to the Government servant until the conclusion of the departmental or judicial proceedings or the enquiry by the Administrative Tribunal, and issue of orders thereon."*

Further the Government Order dated 28.07.1989 issued by U.P. Government reveals that the relevant abstract pertaining to the procedure

in order to make other payment except the Government accommodation reads as follows:-

"(ख) सरकारी भवन के अतिरिक्त अन्य देयों के सम्बन्ध में कार्यवाहीः

(1) सिविल सर्विस रेगुलेषन्स के अनुछेंद 470 बी में यह प्राविधान है कि किसी सरकारी सेवक को पेंषन स्वतः देय नहीं होते जब तक कि उसकी सेवा पूर्णतः संतोषजनक न पायी गयी हो। ष्षासनादेष दिनांक 13/12/1977 में यह निर्णय लिया गया था कि इस प्रविधान का सहारा केवल अपवाद रूपरूप मामलों में ही लिया जायेगा और यह आवष्यक नही होगा कि पेंषन सम्बन्धी समस्त मामलों को विभागाध्यक्ष अथवा नियुक्ति प्रधिकारी के पास भेजा जाय। उक्त शासनादेष में यह प्राविधान कर दिया गया था कि सेवानिवृत्ति की तारिख में आठ महीने पहले पेंषन प्रपत्र अग्रसारण करने वाले अधिकारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी से इस तथ्य की पूछताछ की जायेगी कि क्या पूर्ण पेंषन प्रपत्र अग्रसारण करने वाले अधिकारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी से ऐसी पूछताछ की जायेगी कि क्या पूर्ण पेंषन मंजूर करने के बजाय कम पेंषन देने का विचार है अथवा कोई कार्यवाही प्रारम्भ करने का विचार है। उक्त शासनादेष में यह भी निर्णय लिया गया था कि यदि नियुक्ति प्रधिकारी से ऐसी पूछताछ का उत्तर प्राप्त न हो या मान लिया जायेगा कि पूरी पेंषन से कम धनराषि स्वीकृत करने की कोई मंषा नहीं है और पेंषन प्रपत्रों को स्वीकृत अधिकारी को भेज दिया जायेगा। उपरोक्त प्रविधान के परिप्रेक्ष्य में अब निर्णय लिया गया हे कि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह कार्यवाही सेवानिवृति के आठ माह पहले की जायेगी और नियुक्ति आधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे वांछित सूचना एक माह के भीतर उपलब्ध करा दें। यदि नियुक्ति प्राधिकारी से एक माह के भीतर ऐसी सूचना प्राप्त नहीं होती है तो और आगे प्रतीक्षा किए बिना कार्यालयाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वे पेंषन प्रपत्र पेंषन स्वीकृत करने हुतु अग्रसारित कर दें।

(2) सिविल सर्विस रेगुलेषन्स के अनुच्छेद 351–ए में यह प्राविधान है कि यदि सरकारी सेवक किसी विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप जाने अनजाने राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुॅचाने का अथवा किसी अन्य गंभीर दुराचरण का दोषी पाया गया हो अथवा किसी न्यायिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप दंडित किया गया हो तो राज्यपाल को अधिकार है कि वह उसकी पूरी अथवा आंषिक पेंषन रोक सकते हैं। ऐसी विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही तब तक प्रारम्भ हुई नहीं मानी जाती है जब तक सरकारी सेवक को आरोप पत्र न दे दिया गया हो । अतः यदि उपरोक्तानुसार कोई कार्यवाही सम्पन्न नहीं की

गयी है तो इस नियम के अन्तर्गत किसी भी सरकारी सेवक की पेंषन न तो रोकी जा सकती है और न ही कम की जा सकती हैं। ऐसी दषा में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ नही की गयी है अथवा पूर्ण नही की गयी है तो उसकी पेंषन रोकने का कोई औचित्य नहीं है और उसके पेंषन प्रपत्र स्वीकर्ता अधिकारी को भेजकर उसे पूर्ण पेंषन स्वीकृत करवा दी जायेगी। केवल सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी से ऐसे देयों की वसूली की जायेगी जिनकी स्थिति सेवानिवृत्ति के दिनांक तक स्पष्ट हो चुकी हों।

(3) ऐसे सरकारी सेवकों को, जिनके विरूद्ध सेवानिवृत्ति के दिनांक को, विभागीय/न्यायिक अथवा प्रषासनाधिकरण की जॉच चल रही हो अथवा प्रषासनाधिकरण जॉच किया जाना अपेक्षित हो शासनादेष संख्या सा 3–1679/दस–80–909–79,दिनांक 28 –10–1980 के अनुसार अंतिम पेंषन का भुगतान कर देया जायेगा किन्तु ग्रच्युटी की पूर्ण धनराषि तब तक रोकी जाकेगी जब तक ऐसी जॉच का परिणाम प्राप्त न हो जाय। ग्रेच्युटी की धनराषि से वह कटौतियॉ की जायेंगी जिनका उल्लेख विभागीय/ प्रषासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप पारित आदेष में किया गया हो। इस प्राविधान के अन्तर्गत स्वीकृत अंतिम पेंषन को अंतिंम रूप से स्वीकृत होने वाली पेंषन से समायोजित कर लिया जायेगा किन्तु यदि अंतिम रूप से स्वीकृत होने वाली पेंषन की राषि अंतिम पेंषन से कम हो अथवा पेंषन स्थायी रूप से किसी निष्चित अवधि के लिए कम कर दी जाय या अस्थगित की जाय तो सरकारी सेवक से कोई वसूली नहीं की जायेगी ।यह प्रविधान अन्य समान्य मामलों में जहॉ अंतिम पेंष्न की धनराषि से आगणन की त्रुटि अथवा अन्यथा किसी अन्य कारण से अधिक पाई जाये, लागू नहीं होगा इस प्रकार के मामलां में अधिक भुगतान की गयी धनराषि अंतिम पेंषन की धनराषि से समायोजित कर ली जायेगी। इस हेतु यदि पेंषनर अपनी पेंषन से एक मुष्त अथवा मासिक कटौती करवाने पर आपत्ति करे तो वांछित रिकवरी राहत की धनराषि से काई विधिक अड़चन नहीं है।''

After having careful reading of aforesaid two Government Orders, it is quite clear that the criminal case pending against the petitioner has not been finalized as yet, therefore, it cannot be presumed at this stage whether the petitioner would be convicted in that case. The

provisions of the regulations provided in the Government Orders itself take sufficient care to protect the interest of the Government and can certainly act in accordance with the said rule provided the employee is found guilty. However, it does not mean that the respondents have the right to withhold the entire amount of pension. Mere pendency of the criminal case against the petitioner is not sufficient to withhold the pension as well as post retrial benefits of the petitioner.

It quite clear that the petitioner was placed under suspension but his suspension was ultimately revoked in the year 1987 and after his suspension was revoked, he worked for another 10 years in the Department.

In view of the aforesaid observation, I am of the view that the respondents should pay the full amount of the pension to the petitioner as well as other post retirement benefits payable to the petitioner. However, the respondents may retain the gratuity to be paid to the petitioner till the final adjudication of the criminal case.

With the aforesaid observations, the writ petition is disposed of finally.

(B.C. Kandpal, J.)

16.06.2005
ASWAL